आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 40 (प्रति रविवार) इंदौर, 23 जुन से 29 जुन 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने

विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन की मांग नहीं की–जयराम

नई दिल्ली(एजेंसी)। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भतृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोडने आए। इससे पहले शिवसेना (यूटीबी) सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के. सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा। सदन की कार्यवाही ढाई घंटे चली। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत विभाजन की अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए हैं। उधर, इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी गठबंधन ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत विभाजन की मांग नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इस मामले में सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहता था। जयराम रमेश ने आगे कहा विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने कोडिकुन्निल सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद ध्वनिमत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इंडिया के घटक दल मत विभाजन पर जोर डाल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे सहमति और सहयोग की भावना के आधार पर मत विभाजन करने के पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री और एनडीए के हावभाव में इसकी कमी देखने को मिली।

आपातकाल की बरसी पर पीएम का कांग्रेस पर निशाना

आपातकाल थोपने वालों को प्रेम जताने का अधिकार नहीं

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान और लोस के पहले सत्र में विपक्ष जहां संविधान को सरकार के विरुद्ध अस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं भाजपा ने भी उसी अस्त्र को और धार देकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। 25 जून, 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल की 49वीं बरसी पर मंगलवार को कहा कि इसके काले दिन याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को खत्म किया और संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल थोपने वालों को संविधान के प्रति प्रेम जताने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के लोगों पर इंदिरा गांधी ने क्रूर अत्याचार किए।

वहीं, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में गोष्ठी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए कहा कि संविधान का रक्षक बनकर घूम रहे विपक्षी नेताओं का मुखौटा जनता के सामने लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया ये वही लोग हैं, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने वाला विधेयक पारित किया, अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे

अमरनाथ यात्रा 29 जून से, बेस कैंप को त्रिस्तरीय सुरक्षा

जम्मू। जम्मू कश्मीर में इस साल 29जून से होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले जम्मू आधार शिविर और इसके आस-पास त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किया गया है। इसकी व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा को सौंपी गई.. है। जम्मू में वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरूआत 29 जून से हो रही है। यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। अमरनाथ गुफा 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। यह यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबे नुनवां-पहलगाम मार्ग और गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल . मार्ग से की जाएगी। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विनोद कमार ने कहा कि यात्रा के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित आधार शिविर के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि जम्मू शहर स्थित आवास एवं पंजीकरण केंद्र पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने राजमार्ग पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है जहां से हर रोज यात्रा गुजरेगी। अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की गयी है और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय कर दिया गया है। दुर्घटनामुक्त यात्रा के लिए भी सभी उपाय किए गए हैं। .24 घंटे निगरानी के लिए 360 डिग्री कैमरे लगाए गए सुरक्षा उपायों के तौर पर पुलिस की सुरक्षा शाखा ने क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम की यात्रा

जुलाई में रूस जा सकते हैं मोदी, राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर दोनों देशों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि, किसी भी देश ने इस यात्रा को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 8 जुलाई को एक दिवसीय यात्रा पर मॉस्को जाएंगे। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने बताया कि पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर मॉस्को में जोर-शोर से तैयारी चल रही है। दोनों पक्ष सहमति से तारीख की घोषणा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और उन्हें उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी थी।

80 प्रतिशत सीमांत किसान झेल रहे जलवायु परिवर्तन की मार

नई दिल्ली(एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर देश के किसानों पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसानों को फसल का नुकसान उठाना पड़ा है। फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट द्वारा डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से किए गए सर्वेक्षण में 21 राज्यों के 6,615 किसान शामिल थे। जिसमें बताया गया है कि 41 प्रतिशत किसान बारिश से, 32 प्रतिशत सूखे से और 24 प्रतिशत किसान लेट मॉनसून से परेशान हैं। रिसर्च से पता चला है कि फसल के नुकसान का प्राथमिक कारण सूखा (41 प्रतिशत), बहुत ज्यादा या बेमौसम बारिश सहित अनियमित वर्षा (32 प्रतिशत) और मॉनसून का समय से पहले वापस चले जाना या देर से आना (24 प्रतिशत) है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने अपनी खड़ी फसलों का कम से कम आधा हिस्सा खो दिया है। असमान वर्षा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित चावल, सब्जी और दाल की फसलें हुई है। वहीं, उत्तरी राज्यों में धान के खेत अक्सर एक सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए लगाए गए पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम बारिश के कारण चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और दालों जैसी विभिन्न फसलों की बुवाई में देरी हुई है। हालांकि, इस रिपोर्ट में तापमान से होने वाले बदलावों के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। साल 2022 में भारत में हीटवेव के शुरुआती प्रकोप ने गेहूं की फसल को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन साल 2021 के 109.59 मिलियन टन से घटकर 107.7 मिलियन टन रह गया था।

संपादकीय

संसद में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा, अब बिना चर्चा पास नहीं होंगे संसद के कानून

तीसरी बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर कांटों का ताज है। नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। 10 साल केंद्र में प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी की सत्ता का यह 24वां साल है। 23 साल तक मोदी का सत्ता में एकछत्र राज रहा है। 23 साल तक सदन में उनके पास पूर्ण बहुमत था। पहली बार वह अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्ष इस समय जोश से भरा हुआ है। भले उसके पास स्पष्ट बहुमत ना हो। लेकिन उसमें इतनी ताकत है, कि वह सरकार से पूरी ताकत से मुकाबला कर सके। सदन के अंदर अब सत्ता पक्ष मनमानी नहीं कर सकेगा। बहुमत के आधार पर कानूनो को हो-हल्ले के बीच पास नहीं करा पाएंगे। कानून पास कराने के पहले सदन के अंदर चर्चा भी करानी होगी। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव होगा, सरकार द्वारा जो भी बिल सदन में पेश किए जा रहे हैं, वह नियम और कानून के तहत पेश हों। उन पर विधिवत चर्चा हो। चर्चा होने के बाद मतदान हो। उसी के बाद बिलों की स्वीकृति प्रदान की जाए। पिछले 10 वर्षों में कई कानून नियम विरुद्ध सदन में पेश किए गए। सदन से उन्हें अध्यक्ष ने पास भी करा दिया। मनी बिल के रूप में ऐसे बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए। जो मनी बिल के रूप में सदन के अंदर स्वीकृत ही नहीं हो सकते थे। पिछले 10 साल में संसद सदस्यों के अधिकार भी सदन के अंदर कम हुए हैं। सरकार के मुकाबले सदन के अधिकार सरकार के पास चले गए। बहुत सारे कानून बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित करा दिए गए। तीन अपराध कानून भी उसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर सदन में कुछ मिनटों के अंदर ध्वनि मत से कानूनों को पास करा दिया गया। इससे अध्यक्ष पद की साख भी पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। अब विपक्ष के पास सदन के अंदर ताकत है। अध्यक्ष भी सदन के अंदर विपक्ष की ताकत को अनदेखा नहीं कर सकता है। सदन के अंदर जो भी बिल पेश किए जाएंगे, वह नियम के अंतर्गत सरकार को अध्यक्ष की अनुमति से पेश करने होंगे। ऐसे बिलों पर संसद के अंदर बहस भी होगी। सभी सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने 10 साल में जो कानून पारित कराए हैं। उनको लेकर विपक्ष समय-समय पर अपनी नाराजी जताता रहा है। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया गया। मजदूरों से संबंधित श्रम कानून, न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून, 3 अपराध कानून, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कटौती, चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून और मनी बिल के तहत जो कानून पास कराए जा रहे थे। संसद में विपक्ष की जो अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही थी। अब उन सारे मामले में टकराव बनना तय है। संशोधन या अन्य माध्यमों से विपक्ष चर्चा करने की हर संभव कोशिश करेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ेगा। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में विपक्ष पेपर लीक, अग्नि वीर, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को तगड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भी विपक्ष के साथ सहमति बनाने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए लोकसभा में चुनाव होगा। जिस तरह की स्थितियां लोकसभा में बनती दिख रही हैं, उसमें एक ज्योतिषी जो इन दिनों देश एवं दुनिया में बड़े चर्चित हैं, उनका नाम है- राजीव नारायण, जिन्होंने भविष्यवाणी की है। भाजपा के खिलाफ जन असंतोष बढ़ेगा। विपक्षी दलों का विरोध भी बढ़ेगा। भाजपा के अंदर ही बगावत होगी। भाजपा के लिए अपनी सत्ता बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह की स्थिति सदन के अंदर बनती हुई दिख रही है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सहयोगी दलों और भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं से जिस तरह की चुनौती मिल रही है, उससे मोदी के लिए सत्ता में बने रहना, दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक के साथ जो विश्वासघात का खेला किया है, उसके कारण नवीन पटनायक भी अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उड़ीसा का असर अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर भी पड़ रहा है। रही सही कसर अयोध्या और राम मंदिर पूरी कर रहे हैं। मुख्य सहयोगी दलों को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए। अध्यक्ष पद भी उन्हें नहीं दिया गया।

वायु प्रदूषण से होती लाखों मौतों के लिये कौन जिम्मेदार?

ललित गर्ग

कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्ता का बड़ा कारण हैं। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है, इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिन्ता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित, चिन्तीत व परेशान करने वाले हैं। वहीं सरकार के नीति-नियंताओं के लिये यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहा है? तनिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता-धर्ता इस दिशा में गंभीर प्रयास करते। सरकार की नाकामयियां ही हैं कि जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बतायी जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से वह प्रदूषण फैला रहा है और किस तरह वे इस जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती है, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती है ताकि एक-दूसरे की छीछालेदर कर सके। प्रदूषण के नाम पर भी कोरी राजनीति का होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहना चिन्ता में डालता है। हालत ये बनते हैं कि कभी-कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं होता है। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का नियमन न होने एवं बढ़ता धूम्रपान जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से 1 लाख 69 हजार बच्चे जिनकी औसत आयु पांच साल से कम बतायी गई है, मौत के शिकार होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इनका समुचित शारीरिक विकास सही ढ़ंग से नहीं हो पाता। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियां से पीड़ित होना हैं। हमारे लिये चिंता की बात यह है कि बेहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है। हर कुछ समय बाद अलग-अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही है? इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेलते हैं। इसका पता तब ज्यादा चलता है जब वैश्विक पर्यावरण संस्थान अपने वायु प्रदूषण सूचकांक में शहरों की स्थिति को बताते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया के पहले बीस प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर दर्ज होते रहे हैं। जाहिर है, हम वायु प्रदूषण के दिनोंदिन गहराते संकट से निपट पाने में तो कामयाब हो नहीं पा रहे, बल्कि जानते-बूझते ऐसे काम करने में जरा नहीं हिचकिचा रहे जो हवा को जहरीला बना रहे हैं।

चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है। उसके बाद उच्च रक्तचाप, कुपोषण तथा तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों का नंबर आता है। दरअसल, गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बड़ी आबादी येन-केन- प्रकारेण जीविका उपार्जन में लगी रहती है, उसकी प्राथमिकता प्रदूषण से बचाव के बजाय रोटी ही है। वहीं ढुलमुल कानूनों, तंत्र की काहिली तथा जागरूकता के अभाव में वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर पहल नहीं हो पाती। मुश्किल यह है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूल, पराली की धुंध और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छंटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजन, वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सरकारें नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालिएपन के कगार पर खड़ी है। और हमारा नेतृत्व गौरवशाली परम्परा, विकास और हर प्रदूषण खतरों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, का नारा देकर अपनी नेकनीयत का बखान करते रहते हैं। पर उनकी नेकनीयती की वास्तविकता किसी से भी छिपी नहीं है, देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के आंकड़े इस वास्तविकता को उजागर करते हुए प्रदूषण की समस्या का कोई दीर्घकालिक और ठोस हल निकालने के लिये चेता रहे हैं।

इन्दौर शहर के यातायात सुधार को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का सख्त रवैया

अधिकारियों के दल के साथ चिलचिलाती धूप में चौराहों का किया भ्रमण : लेफ्ट टर्न चौड़ा करने, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी सुधार सहित अन्य बाधाएं हटाने के दिये निर्देश

इन्दौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर इंदौर शहर में यातायात सुधार की विशेष पहल की जा रही है। इसी के तहत शीघ्र ही शहर के अनेक चिन्हित चौराहों पर यातायात सुगम होगा। चिन्हित चौराहों पर लेफ्ट टर्न चौड़ा करने, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी सुधार करने सहित अन्य बाधाएं हटाने के कार्य शुरू किये जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ शहर के अनेक चौराहों का भ्रमण किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चौराहों पर यातायात सुधार एवं वाहनों की आवाजाही की सुगमता के लिए शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दें।

इस अवसर नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, डीसीपी ट्रॉफिक श्री अरविंद तिवारी, अपर आयुक्त नगर निगम श्री अभिलाष मिश्रा, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लौवंशी सहित नगर निगम, ट्रॉफिक पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अपने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यातायात सुधार के संबंध में चौराहों के लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने, चौराहों पर बनी रोटरी में आवश्यक सुधार करने, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी तथा अन्य बाधाएं दूर करने के कार्य जल्द शुरू किये जाये। इसमें विशेषज्ञों की मदद भी ली जाये। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों सम्पन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौका मुआयना कर चौराहों पर यातायात सुगम बनाने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में आज यह चौराहों का निरीक्षण किया गया।

इस कार्य के लिए ट्रॉफिक पुलिस द्वारा प्राथमिकता के साथ मुख्य रूप से 10 चौराहों का चयन किया गया। इसमें से कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकारियों के दल के साथ बिचौली हप्सी बायपास चौराहा, रेडिसन चौराहा, सत्य साईं चौराहा, विजय नगर चौराहा, बापट चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, इंडस्ट्री हाऊस चौराहा तथा राजवाड़ा चौराहा का भ्रमण किया। इन चौराहों पर आवश्यकता के अनुसार सुधार कार्य करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही शहर के जीपीओ एवं अग्रसेन चौराहों पर भी सुधार के कार्य अतिशीघ्र किये जायेंगे।

जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाये जाने पर शहर के तीन व्यावसायिक भवन सील

इन्दौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर इंदौर के बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक संस्थानों/भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित कराये जा रहें है। अग्नि सुरक्षा प्रबंधों में लापरवाही तथा लेतलाली करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज भ्रमण के दौरान अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाये जाने पर शहर के तीन व्यवसायिक भवन सील किये गये हैं।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जूनी इंदौर श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि आज जिन व्यवसायिक भवनों को सील किया गया उनमें सपना संगीता क्षेत्र के विक्रम टावर और स्टाइल अप टॉवर तथा मधुमिलन क्षेत्र के ग्रेस कबीर टावर शामिल है। शहर के बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक संस्थानों/भवनों के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंध शीघ्र ही करा लें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

रोजगार मेले में 273 युवाओं को मिली नौकरी

इन्दौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की 12 कंपनियों में नौकरी के लिए 273 युवाओं को चयन किया गया। मेले में कुल 480 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। उपसंचालक रोजगार श्री पीएस मंडलोई ने बताया कि आयोजित रोजगार मेले में कुल 12 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। इस आधार पर लेकर प्राम्भिक रूप से 273 युवाओं का चयन हुआ। इनका चयन सेल्स एग्जीक्यूटिव, पेकेजिंक, काउंसलर, मार्केटिंग, लेखा सहायक, सुरक्षागार्ड, एच.आर. टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, बेक ऑफिस, ट्रेनी, हेल्पर आदि पदों के लिए किया गया। मेले में जाना स्माल फाइनेंस, एसजीएस मेन पॉवर, जस्ट डायल, चाट पुचका फूड, न्यू ट्रोन बैग, झील मेन्स वेयर, इंस्टा कनेक्ट, बी एबल, सोलर माइंस, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन, चेनल प्ले तथा एसएनटी रीमोट कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं का चयन नौकरी के लिए किया।

रेसीडेन्सी एरिये के राजस्व सर्वेक्षण का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा : भूस्वामियों को मिलेगा अनेक सुविधाओं का लाभ

कलेक्टर आशीष सिंह ने समीक्षा बैठक ली

इन्दौर। इंदौर नगर के रेसीडेंसी एरिया के राजस्व सर्वेक्षण का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब प्राप्त दस्तावेजों के संबंध में दावे आपत्ति बुलाये जाने की प्रक्रिया होगी। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने पर भूमिस्वामियों को अनेक राजस्व सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

इंदौर नगर अंतर्गत स्थित अनसर्वेड रेसीडेन्सी एरिया जो कि वर्तमान में तहसील जूनी इन्दौर के रेसीडेन्सी एरिया, पटवारी हल्का नं. 3 कस्बा इन्दौर के अंतर्गत आता है। जिसका भौगोलिक रकबा लगभग 1030 एकड हैं, जो कि वर्तमान में अनसर्वेड एरिया है। जिसका भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस एरिये के ड्रोन फ्लाई एवं ग्राउण्ड ट्रूथिंग कर प्रारूप नक्शों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है।

इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी और सर्वेक्षण के लिए गठित दलों के सदस्य मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि यह इंदौर शहर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र का पहली बार राजस्व सर्वेक्षण हो रहा है। यह कार्य वर्षों से लंबित था। राजस्व अधिकारियों की मेहनत और लगन से यह कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। जल्द ही यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। बैठक में बताया गया कि प्रारूप नक्शे को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रथम प्रकाशन के पश्चात दावे आपत्ति मंगाकर उनका निराकरण किया जायेगा। बैठक में बताया गया कि राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर रेसीडेन्सी एरिया के भूमिधारकों को इसका सीधे-सीधे लाभ प्राप्त होगा। भूमि के नामांतरण, सीमांकन संबंधी समस्याओं का निराकरण, क्रय-विक्रय में सुगमता, विवाद रहित स्वामित्व स्थापित करना, भू-अर्जन में आसानी, राजस्व सम्बन्धी प्रकरणो के निराकरण में आसानी, पेपरलेस लैंड रिकॉर्ड हेतु सुविधाजनक है, साथ ही सार्वजनिक उपयोग के रास्तों का संरक्षण एवं निर्धारण में आसानी एवं निस्तार की भूमि/शासकीय भूमि को आसानी से संरक्षण किया जा सकेगा।

मप्र बनेगा बेमिसाल- दिखेगा डबल इंजन सरकार का दम

भोपाल। मप्र विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद मप्र में डबल इंजन सरकार का दम दिखेगा। यानी केंद्र सरकार की योजनाओं और सहयोग मिलने से मप्र में और तेजी से विकास होगा तथा मप्र बेमिसाल बनेगा। वहीं प्रदेश में आगामी एक वर्ष में अधोसंरचना विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूंजीगत निवेश बढ़ाएगी। मोहन सरकार भी बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान करने जा रही है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि होगी। इससे सडक़, सिंचाई, बिजली सहित अन्य विभागों की प्राथमिकता वाली अधोसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं को गति दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र सबसे आगे है। अब मप्र सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। यानी सरकार को अपने निर्धारित लक्ष्यों को तो पूरा करना ही है, साथ ही विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए मोहन यादव मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और मंत्रियों को संकल्प पत्र -2023 की घोषणाओं और वचनों को पूरा करने और उसे जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंची है और करीब 50 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा करते हुए मोहन यादव सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर प्रदेश के 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है।

केंद्रीय योजनाओं से लाभ उठाने का निर्देश

उधर, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा है कि केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए समय से प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किए जाएंगे। वे स्वयं भी अलग अलग मंत्रियों से भेंट करके प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। दरअसल, केंद्रीय योजनाओं में अब तक प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। केंद्र सरकार ने पांच वर्ष में तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख तीन हजार 960 और शहरी क्षेत्रों में सात लाख 88 हजार 140 आवास बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से एक लाख 22 हजार आवास बनेंगे, जिनकी शुरुआत भी हो चुकी है। जल जीवन मिशन में 70 लाख 14 हजार 609 नक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के चौथे चरण के लिए एक हजार 630 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सीएम का फोकस विकास पर

डॉ.मोहन यादव ने सीएम बनते ही पुराने मामलों की फाइलों को निपटाने में भी सक्रियता दिखाई। उन्होंने सबसे पहले इंदौर की प्रसिद्द हुकुमचंद्र मिल के मजदूरों को उनके बकाया राशि देने संबंधी फाइल को आगे बढ़ाया और राशि मिलने के प्रक्रिया को पूरा किया। किसानों की समृद्धि के लिए खेती में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए लंबे समय से लंबित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना के करार पर राजस्थान के साथ एमओयू किया। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में यातायात की सुगमता के लिए बीआरटीए कॉरिडोर को हटाने संबंधी निर्णय लेकर क्रियान्वयन भी प्रारंभ कराया। मोहन यादव सरकार के 6 माह के कार्यकाल में लगभग 3 माह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रही। इस दौरान कोई नया काम नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले जो शुरुआत की उनके बारे में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि नामांकन, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व के लाखों अविवादित लंबित मामलों के निराकरण के लिए अभियान चलाया गया और 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो गया। राज्य शासन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, डबल इंजन सरकार का यह संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। शासन की जन हितैषी योजनाएं- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचने लगी।

मप्र को 90 हजार करोड़ से अधिक मिलेंगे

मप्र में अधोसंरचना विकास सहित अन्य कार्यों में आर्थिक बाधा भी नहीं आने वाली है। क्योंकि केंद्र सरकार से विभिन्न करों के हिस्से में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। इसमें केंद्रीय सहायता अनुदान 41,884 हजार करोड़ रुपये का रहेगा। अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में यह 46 हजार 800 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में 15 प्रतिशत बढ़ाकर 56 हजार 256 रुपये किया गया। अब इसे 60 हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार की भी मंशा है कि प्रदेशों में पूंजीगत निवेश बढ़ाया जाए ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़ें और अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसके लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान भी अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने किया है। इसका कुछ हिस्सा प्रदेश को भी मिलेगा, जिससे अधोसंरचना विकास की गाड़ी और तेजी के साथ दौड़ेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की गडकरी से मुलाकात

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अजयगढ़ से जबलपुर मार्ग (राजमार्ग क्र.-55) के राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन एवं खजुराहो से कांलीजर-प्रयागराज मार्ग के निर्माण के संबन्ध में आग्रह किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

फर्जी हस्ताक्षर से करोडों का घोटाला करने वाला कर्मचारी बर्खास्त

भोपाल । राजधानी में एक सहायक वर्ग तीन कर्मचारी को फर्जी हस्ताक्षर कर करोडों रुपए का गबन करने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। कर्मचारी पर सात करोड़ 59 लाख 51 हजार रुपये का घोटाला करने का आरोप है। सेवा से बर्खास्त कर्मचारी केंद्रीय कारागार भोपाल में बंद हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के तत्कालीन संयुक्त संचालक अनिल कुमार गोंड के फर्जी हस्ताक्षर करके सात करोड़ 59 लाख 51 हजार रुपये का घोटाला करने वाले निलंबित सहायक-वर्ग तीन राम सिंह रायपुरिया को बर्खास्त कर दिया गया। नगरीय विकास आयुक्त भरत यादव ने विभागीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की। गबन की राशि की वसूली हितग्राही खाताधारकों से नहीं की जा सकेगी तो उसकी भरपाई सेवा शर्तों के अनुसार भू-राजस्व के बकाया की तरह होगी। नगरीय विकास आयुक्त ने बताया कि विभागीय जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित किया गया है कि रायपुरिया ने ही कुल 33 कूटरचित पत्र तैयार करके तत्कालीन संयुक्त संचालक अनिल कुमार गोंड के फर्जी हस्ताक्षर करके राशि स्वयं व अपने रिश्तेदारों के खातों में हस्तांतरित की।रायपुरिया द्वारा नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा लिंक रोड क्रमांक एक में संधारित बचत खाते से कूटरचना कर राशि स्वयं, अपने रिश्तेदारों एवं अन्य व्यक्तियों के खाते में हस्तांरित की थी। उनके विरुद्ध दिसंबर 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406,409, 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल में चल रहा है।

लोकतंत्र सेनानियों की देश व संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को नमन-मुख्यमंत्री डॉ.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल के कठिन काल में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों की देश के प्रति प्रतिबद्धता को नमन है। उनकी जीवटता के बल पर ही लोकतंत्र को देश में पुनर्स्थापित किया जा सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले

बैठक वंदे मातरम के गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष का स्मरण करते हुए दिवंगत सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार देश में सुशासन स्थापित कर रही है।

मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की

50 लाख किसानों पर कांग्रेस की नजर, सहकारी संस्थाओं के चुनावों में लगाएगी जोर, खोई जमीन पाने की कोशिश

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा और फिर लोकसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने में जुटी हुई है। पार्टी का ध्यान अब सहकारी संस्थाओं के चुनाव पर है। 4 चरणों में होने जा रहे 4543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव में कांग्रेस जोर लगाएगी। इसके लिए सहकारी संस्थाओं से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, राज्य सभा सदस्य अशोक सिंह और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव की समिति बनाई गई है, जिसकी बैठक 28 जून को भोपाल में होगी। प्रदेश की सहकारी समितियों से 50 लाख किसान जुड़े हुए हैं। वर्ष 2013 के पहले तक कांग्रेस का अधिकतर सहकारी समितियों पर कब्जा होता था, लेकिन धीरे-धीरे भाजपा ने इसकी ताकत को समझा और अधिकतर समितियों पर उसका कब्जा होता गया।

आपातकाल की संघर्ष गाथा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष जनता की लड़ाई, जनता के लिए, जनता द्वारा लड़े जाने का उदाहरण है

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल की संघर्ष गाथा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। आपातकाल के कष्टों से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से तत्कालीन परिस्थितियों, दमन और लोकतंत्र सेनानियों की जीवटता का उल्लेख पाठ्यक्रम में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन को मुख्यमंत्री निवास में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पधारे लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर तथा भारत माता, नानाजी देशमुख और श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकतंत्र सेनानियों का प्रादेशिक सम्मेलन वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास मुख्यमंत्री का निवास नहीं, अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक भाग है, और लोकतंत्र सेनानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री निवास में ससम्मान आना उनका अधिकार और सेनानियों का स्वागत व सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लोकतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री निवास पधारे, यह हमारा सौभाग्य है।

लोकतंत्र सेनानियों को मिलेंगे अनेक सुविधाएं-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाऊस और विश्राम गृह में तीन दिन तक रूकने की सुविधा तथा किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। जिन लोकतंत्र सेनानियों को अब तक ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें ताम्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों को पास दिखाने पर टोल नाकों पर भी छूट रहेगी। उनके आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज पर हुए व्यय के भुगतान में विलम्ब नहीं होगा। क्लेक्टर द्वारा तीन माह में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। गंभीर स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में उपचार के लिए बड़े अस्पताल या अन्य महानगर जाने के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलाब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में आरंभ एयर टैक्सी सुविधा के अंतर्गत किराए में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों की राष्ट्रीय सम्मान के साथ अत्येष्ठी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अंत्येष्ठी के समय दी जाने वाली आठ हजार रुपए की राशि को दस हजार रुपए किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के सदस्यों को उद्योग धंधे लगाने अथवा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनीं सरकार देश को विश्व में गौरवान्वित कर रही है-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार, भारत के लोकतंत्र को सम्पूर्ण विश्व में गौरवान्वित कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में लोकतंत्र सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की दमनकारी नीतियों से सभी परिचित हैं। आपातकाल के काले दौर में लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष कर लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में स्थापित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पड़ोसी देशों में जहां लोकतंत्र की हत्या हो गई, वहीं भारत में लोकतंत्र सेनानियों की अनुशासित सेना और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ और देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं निरंतर जारी रहीं। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा घर-घर जाकर राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हुआ। परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अनुसूचित जनजाति की बहन को राष्ट्रपति बनते हुए सम्पूर्ण विश्व ने देखा और सराहा।

लोक सभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने पहले भाषण में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद किया-मुख्यमंत्री डॉ.यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने पहले भाषण में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद करते हुए उन्हें नमन् किया और कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुचारू संचालन उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है। यह जनता की लड़ाई, जनता के लिए, जनता द्वारा लड़े जाने का उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने जिन उद्देश्यों के लिए संघर्ष किया था वह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। धारा 370 का हटना, तीन तलाक, सुशासन आदि इसके प्रतीक हैं। विविधता वाले देश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इतनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कीं इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

लोकतंत्र सेनानियों का किया गया सम्मान-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने शाल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति समर्पण, राजनीतिक संघर्ष और उनके द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा, अजय विश्नोई, रामकृष्ण कुसमरिया तथा मेघराज, कैलाश सोनी, माखन सिंह, अशोक पांडे, सूर्यकांत केलकर और सुरेश देशपांडे का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया तथा लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनके संघर्ष का उल्लेख किया गया।

3 जुलाई को पेश होगा मध्यप्रदेश का बजट

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश विधानसभा का एक जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख तय हो गई है। डॉ. मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। इसके पहले वित्त विभाग बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। विधानसभा सचिवालय ने 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए अब तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में 4 माह का अंतरिम बजट पारित हुआ था।

4 और 5 जुलाई को होगी बजट पर चर्चा-विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्य

होंगे। जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद 3 जुलाई को एमपी सरकार का बजट पेश होगा। इसमें वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2024-25 के आय व्यय का विवरण पेश करेंगे। साथ ही, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की जानकारी सदन के पटल पर सुबह 11.05 बजे रखेंगे। चार जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद बजट पर चर्चा होगी और बजट पर चर्चा का यह क्रम पांच जुलाई तक चलेगा। पांच जुलाई को ही अशासकीय संकल्प और विधेयक पेश किए जाएंगे। 8 जुलाई से होगा विभागों की मांगों पर मतदान- 6 और 7 जुलाई को अवकाश के बाद 8 जुलाई से विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान विभागीय मांगों पर मतदान कराया जाएगा और यह प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी। 12 जुलाई को ही अशासकीय संकल्प और विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इसके बाद 13 व 14 जुलाई को अवकाश के बाद 15 व 16 जुलाई बजट पर चर्चा होगी, और 16 को बजट को मंजूरी दी जाएगी। 17 जुलाई को अवकाश के बाद 18 और 19 जुलाई को शासकीय विनियोग विधेयकों पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों ने सोमवार अंतिम तारीख तक 4500 सवाल पूछे हैं। 14 दिन तक चलने सत्र में 80 ध्यानाकर्षण के भी मामले शामिल रहेंगे।

मोदी का संकल्प- एक पेड़ मां के नाम इंदौर के 51 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ करेंगे शाह

भोपाल। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के महाभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में शाह को निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मप्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत साढ़े पांच करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। अभियान 7 जुलाई से इंदौर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में शुरू हो रहा है।

नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, मध्यप्रदेश पुलिस तैयार

भोपाल (एजेंसी)। देश भर में एक जुलाई से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पुलिस तैयार है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी के संबंध में बुधवार को डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी श्री सक्सेना ने कहा कि नए कनूनों की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा ऑनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण को कॉन्टेबल स्तर तक भी पहुंचाया गया। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ टेबल्स बनाई गई है, जिसकी मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को समझा जा सकता है। यह डिटेल टेबल्स कल तक पूरे प्रदेश में हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में होना सुनिश्चित करें। हर थाने में पूरा एक्ट उपलब्ध हो । कार्यक्रम आयोजित कर करें नए कानूनों का क्रियान्वयन-डीजीपी श्री सक्सेना ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार इन कानूनों को लेकर व्यापक जन जागरुकता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को प्रदेश के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जाए। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करें। सभी एसपी से की वन टू वन चर्चा-डीजीपी श्री सक्सेना ने एडीजी/आईजी, रेंज डीआईजी एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों से नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियों के संबंध में वन टू वन चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। आरक्षक स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी हो। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर आगामी दिनों में और भी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें।

श्रेया पिलगांवकर IFFLA 2024 जूरी पैनल में हुई शामिल

अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर को प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म महोत्सव लॉस एंजिल्स 2024 में शॉर्ट्स श्रेणी के लिए जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, श्रिया ने कहा, मैं लॉस एंजिल्स 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव में लघु फिल्म श्रेणी के लिए जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित होने पर सम्मानित और रोमांचित हूं। मैं लॉस एंजिल्स में होने वाले इस महोत्सव में भाग लेने और उभरते दक्षिण एशियाई फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई इन शानदार शॉर्ट्स को देखने के लिए उत्सुक हूं। मिर्जापुर, और जैसी सीरीज में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली श्रेया पिलगांवकर ने ब्रिटिश सीरीज बीचम हाउस और फ्रेंच फिल्म अन एलस उन जैसी परियोजनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

लॉस एंजिल्स 2024 का भारतीय फिल्म महोत्सव 27 जून से शुरू होने वाला है और 30 जून तक चलेगा। इस महोत्सव में कई बेहतरीन Short films दिखाई जाएंगी।

श्रद्धा कपूर पर आया फैन का दिल

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की क्यूट और चुलबुली एक्ट्रेस में एक हैं। आशिकी 2, साहो, एक विलेन, छिछोरे और बागी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर जबरदस्त लाइमलाइट में बनी हुई हैं। हाल ही में स्त्री 2 एक्ट्रेस ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग एक तस्वीर शेयर की थी, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई हैं। वहीं अब इन सब के बीच श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद उन्हें एक फैन ने प्रपोज किया है।

खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए श्रद्धा कपूर ने लिखा, किस किस को बारिश पसंद है? जैसे ही उन्होंने तस्वीर पोस्ट की, प्रशंसकों ने मजेदार रिएक्शन कमेंट सेक्शन में देने शुरू कर दिए और उनमें से कुछ ऐसे भी यूजर थे जिन्हें अभिनेत्री से

जवाब मिला। वहीं एक फैन ने श्रद्धा कपूर को अलग अंदजा से प्रपोज करते हुए लिखा, यीशु पानी को शराब में बदल सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी शराब में बदलना चाहता हूं। श्रद्धा ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, इस लाइन के लिए, आपको जुर्माना भरना होगा। एक और ने कमेंट किया, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। जिस पर श्रद्धा ने अपने फनी अंदाज में जवाब दिया, प्यार होता है दीवाना सनम।

सारा को आई सुशांत सिंह राजपूत की याद

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ से की थी, जिसमें उनके साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। उस समय दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आई थी, लेकिन किस्तम का फेर देखो इस फिल्म की तीन साल बाद यानी साल 2020 में सुशांत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने को-स्टार्स से लेकर फैंस के दिलों में अपनी अच्छी यादें छोड़ गए, जिनको आज भी फैंस और उनके को-स्टार्स याद करते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की चौथी पुण्यतिथि थी। हाल ही में सारा अली ने अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत को याद करते हुए अपनी पहली फिल्म केदारनाथ के सेट से एक बेहद प्यारी सी तस्वीर शेयर की और एक्टर को याद किया। उन्होंने इस पोस्ट के साथ कई इमोजी भी शेयर किए, जिनमें हाथ जोड़े हुए, एक सौर मंडल, एक ग्रह और एक कैमरा शामिल हैं। इसके साथ ही सारा से हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी सुशांत सिंह को याद किया और उनके साथ अपनी पसंदीदा यादों को ताजा किया। इस दौरान एक्ट्रेस की आंखें भर आईं।

रिमी सेन ने खुद से किया अपना करियर बर्बाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमा सेन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। आखिरी बार वो शॉर्ट फिल्म लोनली गर्ल में नजर आई थी। रिमी सेन ने आखिर क्यों 13 साल पहले इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया इसपर उन्होंने खुलकर बात की है। चलिए जानते हैं अभिनेत्री ने क्या कहा है...

आपको बता दें कि रिमी सेन ने साल 2003 में फिल्म हंगामा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस दौरान लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की थी। इस फिल्म के बाद रिमी सेन ने कई फिल्मों में लगातार काम किया। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। इस दौरान उन्होंने बिग बॉस 9 में भी हिस्सा लिया।

रिमी सेन ने सलमान से नहीं मांगी मदद

रिमी सेन ने सलमान खान के साथ फिल्म क्योंकि में काम किया था। ऐसे में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सलमान से मदद नहीं ली। ऐस में रिमी सेन कहती हैं कि सलमान सच्चे जेंटलमैन और खूबसूरत इंसान हैं। उनका स्वभाव काफी अच्छा है लेकिन फिर भी मैंने कभी काम के लिए उन्हें अप्रोच नहीं किया। रिमी सेन का कहना है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती हूं। रिमी सेन का कहना है कि उनके नसीब में होगा तो काम उन्हें मिल ही जाएगा। वह सलमान को प्रेशर नहीं देना चाहती थी। इसलिए कभी भी उन्होंने सलमान से मदद नहीं मांगी।

पानी पीते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां

पानी पीते समय कुछ गलतियां की जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यहां कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें अपनी सेवा समय पानी पीते समय नहीं करनी चाहिए।

बात करते समय

पानी पीते समय अगर हम बात करते हैं तो हमें अनुचित चबावन से बचना चाहिए। यह न केवल आपके बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी आपकी संभाषण क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

गलत समय पर पानी पीना

खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना पचने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए, खाना खाने के तुरंत बाद कुछ समय इंतजार करें और फिर पानी पिएं।

धीरे-धीरे पानी पीना

पानी को धीरे-धीरे पीना चाहिए और उसे चबावन के साथ निगलना चाहिए।

इससे आपका शारीर सही ढंग से पानी को सोख सकता है और पाचन क्रिया को अच्छी तरह से सहायता मिलती है।

ठंडे पानी का सेवन

ठंडे पानी का सीधा सेवन करना नहीं चाहिए, विशेष रूप से जब आप ठंडे मौसम में हैं या गर्मी के दिनों में। ठंडे पानी सेवन करने से आपके शरीर का तापमान अचानक गिर सकता है, जिससे आप आराम से नहीं पी सकते हैं। संयमित और सही तरीके से पानी पीने से आपके शारीर को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति होगी और आप स्वस्थ रहेंगे।

इन महिलाओं को ज्यादा होता है किडनी डिजीज का खतरा

किडनी से संबंधित परेशानियों का सामना किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में करना पड़ सकता है, लेकिन महिलाएं इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद अधिकतर महिलाओं को किडनी से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

उम्र

महिलाओं में उम्र के साथ किडनी के संबंधित समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ, किडनी की कार्यशीलता में कमी हो सकती है और किडनी की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, जिससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

डायबिटीज

डायबिटीज महिलाओं में किडनी संबंधित समस्याओं का मुख्य कारण हो सकता है। उच्च रक्त शर्करा स्तर के कारण, किडनी के रक्त संचार में कमी हो सकती है और किडनी को क्षति पहुंच सकती है।

हार्ट रोग

हृदय रोगों के मौजूद होने पर किडनी पर अस्पष्ट प्रभाव पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप, अवसाद या अन्य हृदय समस्याएं किडनी के संबंधित स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं।

विटामिन और मिनरल

आपूर्ति में विटामिन और मिनरल की कमी किडनी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। विटामिन डी, बी-कॉम्प्लेक्स या उपादानों की कमी से किडनी संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

खराब फिजिकल हेल्थ से बिगड़ रही है मैरिड लाइफ

तो रोज करें ये योगासन

योग से पुरुषों और महिलाओं में हो रही इनफर्टिलिटी या इससे जुड़ी दूसरी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इन योगासन को करके आप ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने समेत कई फायदे पा सकते हैं। इनका बड़ा फायदा आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव से नजर आता है। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और इसी कारण आज लोग पूरी दुनिया में योग का महत्व समझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि योग हमारी सेक्स लाइफ को भी दुरुस्त बनाने में कारगर है। खराब लाइफस्टाइल, शराब, स्मोकिंग या दूसरी चीजों के चलते पुरुषों में पिता न बन पाना या दूसरी समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद तक कर देती हैं। हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे इन योगासन को करके आप ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने समेत कई फायदे पा सकते हैं।

भुजंगासन

इस योगासन को करने से हमारी रीढ़ और पेल्विक को फायदा होता है। इसे करने से आप पेल्विक में संतुलन बना पाते हैं। इसे करने के लिए मैट पर उल्टे लेट जाएं और फिर हल्का सा ऊपर की तरफ उठें। इस दौरान आधे शरीर को लिटाए ही रखें और ऊपर की तरफ देखें।

अधोमुख श्वानासन योग

इसके लिए जानवर की तरह खड़े हो जाएं और आगे की तरफ झुकें। योग मैट पर लेट जाएं और फिर सांस को खींचते हुए पैरों और हाथों के बल पर शरीर को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए इसी एंगल में खुद को आगे की तरफ निकालें। ध्यान रहे कि इस योग को करते हुए हाथ और कंधे सीधे रहें।

सर्वांगासन

शरीर के कुछ हिस्सों में आई सूजन को कम करने के लिए इस योग मुद्रा को करना चाहिए। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और फिर पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश करें कि पैर हवा में सीधे रहें और अपना पूरा वजन कंधों पर टिका दें। शुरू में इस आसन को करने में दिक्कतें हो सकती हैं, पर एक बार आदत पड़ जाए तो काफी फर्क नजर आने लगता है।

बिटिलासन

इसे गाय योग मुद्रा भी कहता हैं जो वार्मअप में काम आती है और इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। इसे करने के लिए मैट पर दोनों घुटनों को टेक कर बैठ जाएं। आप इसे करने के लिए वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों का फर्श पर टिकाएं और आगे की तरफ देखें। अब हाथों पर वजन डालें और कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएं।

जीभ देखते ही डॉक्टर कैसे लगा पाते हैं बीमारी का पता जानें इसके पीछे का साइंस

शरीर में कोई भी गड़बड़ी होने पर हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर भी झट से हमारी जीभ को देखकर बीमारी का पता लगा लेता है। हम दवा लेकर घर का रुख कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर डॉक्टर जीभ में ऐसा क्या देखता है, जिससे वो हमारे शरीर की बीमारी के बारे में पता लगा लेता है। दरअसल में डॉक्टर जीभ में बदलावों को देखकर शरीर में पनप रही बीमारियों का पता लगा लेते हैं। जीभ के कलर और रंगत को देखकर डॉक्टर को पता चल जाता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है।

जीभ से कैसे होती है बीमारी की पहचान-

रंग और एनीमिया-

डॉक्ट के पास जाने पर वो सबसे पहले हमारी जीभ देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि परेशानी क्या है. इस दौरान डॉक्टर दरअसल में चीभ का रंग देखते हैं। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप शरीर में खून की कमी तो नहीं है। सामान्य तौर पर हमारी जीभ का रंग गुलाबी होता है, लेकिन खून की कमी पर इसका रंग बदल जाता है और ये पीला हो जाता है साथ ही जीभ चिकनी हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपकी जीभ का रंग गुलाबी नहीं है तो आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह में छाले और मुंह का सूखना आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।

जीभ में दरारें पड़ना-

विशेषज्ञों की मानें तो जीभ में दरारें शरीर में विटामिन की कमी या इन्फेक्शन को दर्शाती है। ऐसी जीभ को फिशर्ड टंग कहा जाता है। जिन लोगों को किडनी रोग, अनियंत्रित डायबिटीज, कीमोथेरेपी आदि की समस्या है उनमें ऐसी जीभ देखने को मिलती है।

जीभ का सफेद होना-

कई बार हमारी जीभ पर सफेद धब्बे या फिर जीभ का रंग सफेद हो जाता है. ये किसी Yeast infection के संकेत हो सकते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं अक्सर उनकी जीभ भी सफेद हो जाती है।

काले धब्बे होना-

यदि आपको आपकी जीभ पर काले धब्बे दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क करें। ये बैक्टीरिया या फंगस इंफेक्शन के चलते हो सकता है। कभी कभी आयरन की दवाई खाने से भी जीभ का रंग काला हो जाता है।

जीभ का लाल होना-

वैसे को हमारी जीभ गुलाबी रंग की होती है, लेकिन कई बार इसका रंग लाल हो जाता है। जीभ का लाल होना शरीर में विटामिन बी 12 की कमी की ओर इशारा करता है। इंफेक्शन और फीवर के चलते भी जीभ का रंग लाल हो सकता है।

इन्दौर मेट्रो 90 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ी

लगभग 3 मिनट में तय की 6 किलोमीटर की दूरी

इन्दौर। मेट्रो ट्रेन का हाई स्पीड टेस्ट किया गया। मेट्रो पहली बार 90 किमी की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। सुपर कॉरिडोर पर मंगलवार देर रात यह टेस्टिंग हुई। इसमें मेट्रो ने 3 मिनट में करीब 6 किमी की दूरी तय की।

इससे पहले ल मेट्रो का पहली बार जब ट्रायल हुआ था, तब 10 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो चली थी। यह ट्रायल मंगलवार रात सुपर कॉरिडोर पर रात 10 बजे बाद शुरू किया। इसके साथ ही अलग-अलग दौर में बुधवार सुबह 6 बजे तक चला। स्पीड टेस्ट के बाद अब ब्रेकिंग, इलैक्ट्रिसिटी व कैमरा की टेस्टिंग होगी। मेट्रो को 80 किमी की स्पीड से चलाकर ब्रेकिंग सिस्टम की जांच होगी। भोपाल में करीब एक माह पूर्व इसी तरह की गति परीक्षण किया जा चुका है। सुपर कारिडोर पर मंगलवार रात 10 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे का समय मेट्रो की स्पीड टेस्टिंग के लिए तय किया गया था। सुपर कारिडोर के जिस हिस्से पर टेस्टिंग की जानी थी, उस हिस्से में काम बंद रखा गया।

रेलवे के आरडीएसओ की अनुमति लेने की तैयारी

मेट्रो प्रबंधन द्वारा दिसंबर तक सुपर कारिडोर के प्रायरिटी कारिडोर पर कमर्शियल रन की योजना है। इसके पहले रेल मंत्रालय के रिसर्च डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) की टीम मेट्रो की टेस्टिंग कर अप्रूवल देगी।

जल्द ही इसके लिए टीम इंदौर आएगी। इसके बाद कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएसए) की टीम भी जांच के लिए इंदौर आएगी। इसके बाद मेट्रो के प्रायरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन शुरू किया जा सकेगा।

इस कारण प्रायरिटी कारिडोर पर मेट्रो चलाने की है जल्दबाजी

मेट्रो प्रबंधन ने दिसंबर में कमर्शियल रन की योजना बनाई हैं। इस हिस्से में यात्री कम मिलने के कारण शहरवासियों व जनप्रतिनिधियों ने इस हिस्से में जल्द मेट्रो का संचालन करने के बजाय गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो बनने पर उसका कमर्शियल रन करने की बात कही। हकीकत यह है कि मेट्रो को सुपर कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से पर चलाने पर छोटे हिस्से में रेलवे की सुरक्षा संबंधित अनुमतियां लेना आसान हैं।

यही वजह है कि मेट्रो के रेडिसन चौराहे तक काम पूर्ण होने का इंतजार करने के बजाय सुपर कॉरिडोर के प्रायरिटी कॉरिडोर को मेट्रो प्रबंधन जल्द शुरू करना चाहता है।

मंत्री का आश्वासन : इंदौर एयरपोर्ट को शीघ्र मिलेगा अंतरराष्ट्रीय दर्जा, नया टर्मिनल और टैक्सी-वे की मांग

इन्दौर। इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार को गति मिलने वाली है। सांसद शंकर लालवानी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर इंदौर एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने के मामले में विस्तृत चर्चा की जिसमें इंदौर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने का आग्रह किया गया। मंत्री ने सांसद को आश्वासन दिया कि पूरी प्राथमिकता से यह कार्य किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से नया टर्मिनल भवन बनाने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही, पैरेलल नया टैक्सी वे जल्द बनाने की मांग की। उन्होंने नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर लगातार बढ़ते हुए इंदौर के बारे में चर्चा की और यहां की हवाई सुविधाओं का विस्तार करने का आग्रह किया और मंत्री ने कहा देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लिए सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई। सांसद ने उन्हें जानकारी दी कि अपने पिछले कार्यकाल में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर इंदौर के नए टर्मिनल भवन की प्रक्रिया को तेज किया था वहीं पैरेलल टैक्सवे बनाने की मांग भी की थी जिसकी अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सांसद शंकर लालवानी ने मंत्री को इंदौर आने का आमंत्रण भी दिया है।

आबकारी विभाग ने पकड़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब

इन्दौर। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश एवम सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर मनीष खरे के निर्देश में, नियंत्रण कक्ष प्रभारी आर एच पचौरी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग इंदौर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है। इसी कड़ी में वृत्त छावनी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरसी डाबर के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा ने हमराह बल के साथ एक दोपहिया वाहन से दो थैलों में 300 पाव (06 पेटी) देशी मदिरा मसाला तथा 50 पाव देशी मदिरा मसाला जब्त किया। कुल मात्रा 350 पाव अर्थात 63 बल्क लीटर अवैध परिवहन करते हुए आरोपी विनोद पिता देवी सिंह चौहान उम्र 27 वर्ष जाति खटीक निवासी 185 गरीब नवाज कॉलोनी छोटा बांगड़दा को पकड़ा। डेली कॉलेज से मूसाखेड़ी चौराहा रोड पर खड़ा हुआ था दौरान गश्त उपरोक्त अनुसार बरामद अवैध शराब को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया।

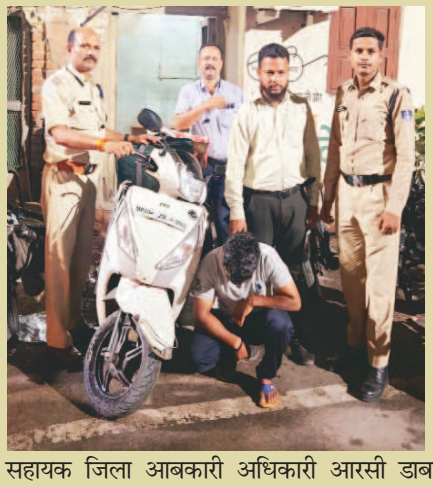

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निर्माण कार्य की प्रगति का मौका मुआयना कर लिया जायजा

इन्दौर। इंदौर के बेस्ट प्राईज के सामने झलारिया में बन रहे देश में अपने तरह के पहले एवं अनूठे फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण अगले वर्ष जुलाई में पूरा होगा। इस ब्रिज के निर्माण पर लगभग 80 करोड रुपये खर्च किये जा रहे है। यह जानकारी आज यहां जल संसाधन श्री तुलसीराम सिलावट द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान दी गई। इस मौके पर श्री सिलावट ने फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति का मौका मुआयना कर जायजा लिया।

इस मौके पर बताया गया कि यह ब्रिज देश में अपने तरह का पहला एवं अनूठा है। यह ब्रिज 6 जंक्शन लेन और 3 लेयर का रहेगा। इस ब्रिज के बन जाने से झलारिया क्षेत्र की लगभग 20 कालोनी एवं 10 गाँवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही इस हाईवे पर निकलने वाले 60 हजार से अधिक नागरिक भी लाभांवित होंगे। स्कूल बसों और अन्य वाहनों के जाम से यह क्षेत्र मुक्त हो जायेगा। शहर में यात्री वाहन के साथ सुगमता से प्रवेश कर सकेंगे। मंत्री श्री सिलावट ने अपने भ्रमण के दौरान नेशनल हाईवे के अधीक्षण यंत्री श्री सुमेश बांझल से ब्रिज निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि ब्रिज निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। यह ब्रिज निर्माण का कार्य अगले वर्ष जुलाई में पूरा हो जायेगा। ब्रिज निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

श्री सिलावट ने कहा कि यह ब्रिज डबल इंजन की सरकार का बेहतर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विकास को नई गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ ब्रिज का निर्माण पूर्ण करें। उन्होंने ब्रिज निर्माण में आ रही छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने तथा आपसी समन्वय के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। श्री सिलावट ने यह भी कहा कि ब्रिज निर्माण के दौरान तथा बारिश में किसी भी यात्री और वाहन चालक को परेशान नहीं होना पड़े ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)